Dharna By employees of Regional Rural Banks

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद सभापति महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मेरा यह विशेष उल्लेख उन्हीं से संबंधित है इसलिए मैं चाहूंगी कि वे मेरा विशेष उल्लेख सुनने के बाद, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए संसद के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं।

सभापति जी, आज संसद मार्ग पर देश भर से आए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि सारे देश में 196 ग्रामीण बैंकों की जो लगभग 15,000 शाखाएं हैं, उन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाए। इसके अलावा वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के साथ विलीन करने का जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया जा रहा है, वह प्रस्ताव ग्रामीण बैंकों के मूल लक्ष्य पर ही एक कुठाराघात के समान होगा और उससे देहातों में लगने वाला पैसा भी शहरों और निगम क्षेत्र के लिए चला जाएगा, इसकी गहरी आशंका है। धरने पर बैठे हुए ये अफसर और कर्मचारी भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मानव संसाधन की जो नई योजना पेश की गई है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। यह योजना पूरी तरह अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक तथा बैंक और उसके उद्देश्यों तथा बैंक में जमाकर्त्ताओं, ऋण लेने वाले और बैंक के कर्मचारियों सभी के हितों की विरोधी है।

सभापति महोदय, ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ये मांगें पूरी तरह से जायज हैं। 1992 में समूची संसद ने एक स्वर से भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के निर्माण की मांग को उठाया था। उसके बाद वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी दिसंबर, 1992 में सर्वसम्मति से NRBI के गठन की सिफारिश की थी। जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में निर्यात, आवास, उद्योग, लघु उद्योग ढांचागत सुविधाओं में सर्वोच्च स्तर के ऋणदाता संस्थान बने हुए हैं लेकिन सिर्फ देहात और कृषि क्षेत्र में ऋणों की जरूरतों के लिए कोई Apex Level Credit Institution नहीं है। नाबार्ड सिर्फ रिफाइनेंसिंग और ऋणों के सुपरविजन का ही काम करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तत्काल NRBI का गठन किया जाए। लेकिन यह सरकार तो बिल्कुल उल्टी दिशा में ही NRBI की संभावनाओं को ही समाप्त करना चाहती है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पिछले साल ही यद्यपि 650 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, 15,000 ब्रांचों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में NRBI के लिए पहले से पूरा एक नेटवर्क मौजूद है। ऐसी स्थिति में NRBI की फाइनेंशियल वॉयबिलिटी के बारे में तो कोई संदेह ही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सदन के जरिए सरकार से यह मांग करूंगी कि ग्रामीण बैंकों के अब तक विकसित समूचे नेटवर्क के लिए मौत का परवाना लिखने के बजाए वह अब तक की स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप तत्काल NRBI के गठन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। धरने पर बैठे हुए ग्रामीण बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी राष्ट्रीय हित के एक बहुत ही अहम् मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी आवाज की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। मैं समझती हूं कि आप आवाज का उत्तर आवाज से देंगे।

DR. A.R. KIDWAI (N.C.T. of Delhi) : Sir, I associate myself with the Special Mention raised by Smt. Sarla Maheshwari.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : मैं एस्सोसियेट करता हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): मैं एस्सोसियेट करता हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : समापति, मंत्री जी, चुप बैठे हुए हैं, कुछ तो कहें।

श्री राजू परमार (गुजरात): कुछ तो रिस्पोंस दीजिये।..(व्यवधान)..

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मंत्री जी कौन सी स्वीकृति में सिर हिला रहे हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं।

THE FINANCE MINISTER (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, on the issue, which has been raised by Smt. Sarla Maheshwari, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक ग्रामीण बैंकों का ताल्लुक है, ग्रामीण बैंक के किसी भी कर्मचारी से आप बात करें तो वह इस बात को स्वीकार करेगा कि 1990-91 में जब मैं अल्प समय के लिए वित्त मंत्री था, उस समय मैंने उनका भला किया था। इस बार, जब मैं वित्त मंत्री बना, तब भी मैंने उनका भला किया। एक बड़ी समस्या उनके वेतन मान की समस्या थी, उस समस्या का हमने समाधान किया है। उस समस्या का समाधान वर्षों से नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक समस्या का समाधान हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि तत्काल दूसरी समस्या को ले कर धरने पर बैठने का काम किया जाए। ...**(व्यवधान)**... नहीं, उसमें देखिये एक ढांचा बना हुआ है ग्रामीण बैंको का, एक सोच थी ग्रामीण बैंकों के उस ढांचे को बनाने के लिए। मैं इस विषय पर तैयारी करके नहीं आया हूं। इसलिए हल्के ढंग से मैं सदन के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ग्रामीण बैंक का ढांचा बना था, वह सोच समझ कर बनाया गया था, ग्रामीण बैंक का जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रख कर उस समय की सरकार के द्वारा बनाया गया था। मैं मानता हूं कि आज भी वह उद्देश्य वैलिड है, सही है और उन्हीं को ध्यान में रख कर आगे जो उनका स्ट्रक्चर होगा, उसको भी हमें तय करना होगा. ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उद्देश्यों के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं? वाणिज्य बैंकों के साथ उनका विलय कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का जो मूल लक्ष्य था, वह लक्ष्य ही धराशायी हो जाता है। वह अपने आप में ही खत्म हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि एक बैंक में सिर्फ चार लोग रहेंगे चाहे वह हैडक्वार्टर हो या ब्रांच हो। पूरी की पूरी जो आपकी मैनपावर प्लानिंग की जो नीति है, वह भी विरोधी है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगी अगर गहराई में नहीं जाते तो आगे जा कर कम से कम उनके विरोध में काम न करें।

Telephone tapping in Tamil Nadu

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, we, the members of the DMK party, strongly condemn the violation of the basic rights by the Government of Tamil Nadu through police officials.